पत्रांक :2P/RGSA-20/Fund-10/2025/ 08(ख)/0 /पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 12/5/26

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (पुनर्गठित) योजना के क्रियान्वयन हेतु पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश मद की रू० 6,00,00,000.00 (छः करोड़ रूपये) मात्र तथा राज्यांश मद की रू० 4,00,00,000.00 (चार करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल रू० 10,00,00,000.00 (दस करोड़ रूपये) मात्र राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को "राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (पुनर्गठित)" नाम से अनुमोदित करते हुए इसे दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2026 तक के लिए प्रभावी किया था, जिसे पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक–M-11015/123/2026-CB दिनांक–06.04.2026 द्वारा योजना का विस्तार 30 सितम्बर, 2026 तक के लिए किया गया है। इस योजना के तहत पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने, विकेन्द्रीकृत संस्था के रूप में पंचायतों की क्षमता विकसित करने एवं पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन हेतु राशि उपलब्ध करायी जाती है। यह योजना केन्द्र प्रायोजित है, जिसमें केन्द्र एवं राज्य की हिस्सेदारी क्रमशः 60:40 है।

2. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–F.No.31/IFD/MoPR/2026-27 दिनांक–23.04.2026 द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (2026–27) के अंतर्गत केन्द्रांश के रूप में कुल रू० 6,00,00,000.00 (छः करोड़ रूपये) मात्र राशि विमुक्त की गयी है, जिसके आलोक में राज्यांश मद की राशि रू० 4,00,00,000.00 (चार करोड़ रूपये) मात्र विमुक्त की जानी है।

3. उक्त के आलोक में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (2025–26) योजना अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की गठित Central Empowered Committee (CEC) द्वारा अनुमोदित गतिविधियों (25 प्रतिशत) का क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्रांश मद की रू० 6,00,00,000.00 (छः करोड़ रूपये) मात्र तथा राज्यांश मद की रू० 4,00,00,000.00 (चार करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल रू० 10,00,00,000.00 (दस करोड़ रूपये) मात्र राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कृ०पृ०उ०

4. इस स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026–27 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से संबंधित बजट शीर्षों से निम्नरूपेण की जायेगी:–

क्र०	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	राशि (रूपये में)
i)	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0215–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विपत्र कोड–16–2515001980215	0215–31–04	1,50,00,000.00
		0215–31–05	1,00,00,000.00
		0215–31–06	1,50,00,000.00
	Total (A)		**4,00,00,000.00**
ii)	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– उप शीर्ष–0214–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विपत्र कोड–16–2515007890214	0214–31–04	90,00,000.00
		0214–31–05	50,00,000.00
		0214–31–06	1,50,00,000.00
	Total (B)		**2,90,00,000.00**
ii)	मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–उप शीर्ष–0220–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)। विपत्र कोड–16–2515007960220	0220–31–06	3,10,00,000.00
	Total (C)		**3,10,00,000.00**
	Total (A+B+C)		**10,00,00,000.00**

दस करोड़ रूपये मात्र

5. इस स्वीकृत राशि का व्यय वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के नये मार्गदर्शिका (पत्रांक–F.No. 1 (27)/PFMS/2020 दिनांक–13.07.2023) के अनुसार RBI के e-Kuber Platform के द्वारा राशि का परिसीमन/अंतरण/व्यय SNA-SPARSH Model के माध्यम से क्रियान्वयन किया जायेगा।

6. इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर क्रियान्वयन एजेंसी (Implementing Agency) परियोजना निदेशक, बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था, पटना होंगे, जो वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु Central Empowered Committee (CEC) द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना का 25 प्रतिशत मात्र गतिविधियों के क्रियान्वयन में राशि का व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।

7. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य स्तर पर नामित क्रियान्वयन एजेंसी (Implementing Agency) हेतु संयुक्त सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार होंगे, जो राशि की निकासी एवं व्यय SNA-SPARSH Model के माध्यम से करना सुनिश्चित करेंगे।

8. इस स्वीकृत राशि को पंचायती राज विभाग, बिहार (प्रशासी विभाग) द्वारा CFMS पोर्टल पर राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एजेंसी (Implementing Agency) को राशि का Limit प्रदान करेंगे। उपलब्ध करायी गयी राशि का भुगतान पूरी छान–बीन एवं जाँच– पड़ताल के बाद ही किया जायेगा। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. इस स्वीकृत एवं आवंटित राशि में से व्यय/उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र (GFR-19A एवं BTC-42A) में विभाग को महालेखाकार के समायोजन हेतु 18 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

10. इस स्वीकृत राशि की निकासी हेतु अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा, जिसके आधार पर राशि की निकासी एवं व्यय की जायेगी।

11. इस स्वीकृत राशि के प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की सहमति संचिका संख्या 2P/RGSA-20/Fund-10/2025 के पृष्ठ संख्या 44/टि० पर दिनांक 29/04/2026 को प्राप्त है।

12. इस स्वीकृत राशि के प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 2P/RGSA-20/Fund-10/2025 के पृष्ठ संख्या 46/टि० पर दिनांक 09/05/2026 को प्राप्त है।

13. इस स्वीकृत राशि के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या 2P/RGSA-20/Fund-10/2025 के पृष्ठ संख्या 46/टि० पर दिनांक 12/05/2026 को प्राप्त है।

14. इस स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

(नजर हुसैन) 12/5/26

अपर सचिव

ज्ञापांक : 2P/RGSA-20/ Fund-10 /2025 / 08(स्वी०) / पं०रा०, पटना, दिनांक 12/5/26

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

(नजर हुसैन) 12/5/26

अपर सचिव

ज्ञापांक : 2P/RGSA-20/ Fund-10 /2025 / 08(स्वी०) / पं०रा०, पटना, दिनांक 12/5/26

प्रतिलिपि : परियोजना निदेशक, बिहार पंचायत संसाधन संस्था, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

(नजर हुसैन) 12/5/26

अपर सचिव

कृ०पृ०उ०

D:\Abhilasha 2026\RGSA\Swikrityadesh.docx

ज्ञापांक : 2P/RGSA-20/ Fund-10 /2025 / 08 (स्वी०) / पं०रा०, पटना, दिनांक 12/5/26

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकःयथा उपर्युक्त।

(नजर हुसैन) 12/5/26
अपर सचिव

ज्ञापांक : 2P/RGSA-20/ Fund-10 /2025 / 08 (स्वी०) / पं०रा०, पटना, दिनांक 12/5/26

प्रतिलिपिः संयुक्त सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा 5 एवं 6 / आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत्यादेश की प्रति विभाग के वेबसाईट पर डालेंगे तथा सभी संबंधितों को ईमेल के माध्यम से सूचित करेंगे।

अनुलग्नकःयथा उपर्युक्त।

(नजर हुसैन) 12/5/26
अपर सचिव

i	Computer Lab in SPRC (30 Computer)	0.23
ii	Computer Lab in DPRC (20 Computers in 24 Districts)	3.74
	Total of special component	**3.97**
6	**Support for Panchayat Infrastructure**	
i	Computer and Accessories (171 @ 78,000/- CO)	1.33
ii	Computer and Accessories (2000@ 78,000/-)	15.60
	Total Cost Panchayat Infrastructure	**16.93**
7	**Programme Management Unit (PMU)**	
i	State Programme Management Unit (SPMU)1 SPM, 1 State coordinator (e.gov) & 1 coordinator (M& E), 1 DEO	0.264
ii	District Programme Management Unit (38 DPMU)(38 DPM, 38 Dist. Coordinator(e.gov/M&E), 38 DEO)	4.10
iii	Block Program Management (295 BPMU)(295 Block Coordinator, 295 DEO/Administrative assistant)	14.16
	Total of PMU	**18.52**
8	**Distance learning facility through SATCOM or IP based technology etc.**	
i	Studio at the State level (Up to Rs.1.00 crore) 1 Studio at State Level	1.00
ii	Satellite Interactive Terminals (SITs) (Rs.1.5 lakh per SIT)	0.58
	Total of Distance learning	**1.58**
9	**Innovative Project**	
ii	Increasing Panchayat's Own Source Revenue	0.00
	Total Innovative Project	**0.00**
10	**Economic Development and Income Enhancement Bihar Projects**	
i	Fertilizer from Water Hyacinth (JalKumbhi)	0.00
	Total of Economic Development Project	0.00
	Sub Total	**174.08**
11	IEC (Upto 2% of the approved plan size)	3.48
12	PMU (Upto 1.5% of the approved plan size	2.61
	Total Plan size	**180.17**

Annexure-V

Budget Summary of Annual Action Plan for Bihar (2025-26)

(Rs. in crore)

Sl. No.	Component	Amount approved by CEC
1	**Capacity Building & Training**	
i	Training for GPDP/ BPDP/ DPDP /Thematic Training - LSDGs (98,474 participants)	23.01
ii	Specialized Training trainings (1,28,525 participants)	23.99
iii	Any other Training (1,55,297 participants)	31.98
	Total (CB&T)	**78.98**
2	**Other activities under Capacity Building & Training**	
i	Training Module	0.10
ii	Training need Assessment	0.10
iii	Development of Training Material	0.20
iv	Evaluation of Capacity building and training activities	0.10
v	Exposure visits within State (for 1000 @ 3500 for 2days)	0.70
vi	Exposure visits outside State (for 4500 @ 5000 for 6 days)	13.50
vii	Development of Panchayat Learning Centre (for 50 PLC)	3.50
viii	Additional Trainers/ Master Trainers in thematic areas for localization of SDGs. (for 35 MTs)	0.04
ix	Leadership Management Development Program (200 participants @10,000/- for 5 days)	1.00
	Total of CB&T (other activities)	**19.24**
3	**Institutional Infrastructure**	
i	Provision for establishment of SPRCs in rented building	0.09
ii	Provision for DPRC Building Construction (1 carry over)	2.00
iii	Provision for establishment of DPRCs in rented Building (14 DPRCs)	0.84
iv	Hiring of Training infrastructure &equipment's at District Level (1% of the cost of total training at District level)	0.36
v	Provision for establishment of BPRCs in rented Building (for 295 BPRCs)	10.62
vi	Hiring of Training infrastructure & equipment at Block Level (1% of the cost of total training at Block level)	0.12
	Total Institutional Infrastructure	**14.03**
4	**Institutional Infrastructure (Recurring Cost)**	
i	SPRC Recurring Cost (9 thematic expert and 2 Administrative staff)	0.84
ii	DPRC Recurring Cost for 38 DPRCs (4 thematic expert and 1 Administrative staff in each DPRCs)	7.60
iii	BPRC Recurring Cost for 240 BPRCs (2 thematic expert and 1 Administrative staff for each BPRCs)	12.39
	Total Institutional Infrastructure (Recurring cost)	**20.83**
5	**Computer Lab in SPRC/DPRC**	

सुशील कुमार लोहानी, आई.ए.एस.
अपर सचिव
Sushil Kumar Lohani, IAS
ADDITIONAL SECRETARY
Tel.: 011-23725301
Email: s.lohani@nic.in

सत्यमेव जयते

75 वर्ष संविधान के

पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार
टावर - II, 9वां तल
जीवन भारती बिल्डिंग,
नई दिल्ली - 110001
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
Tower-II, 9th Floor
Jeevan Bharti Building
New Delhi - 110001

F.No: M-11015/123/2026-CB

Dated: 06th April, 2026

To

The ACS/Principal Secretaries/Secretaries
Department of Panchayati Raj
All States/Union Territories

Subject: Continuation of activities and Human Resources under Revamped Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) till further orders

This is in reference to continuation of activities and Human Resources under Revamped RGSA for the current Financial Year 2026-27.

2. In this regard, attention is invited to the instructions issued by the Department of Expenditure vide OM No. 42(02)/PF-II/2014 dated 23.03.2026 regarding appraisal and continuation of schemes beyond 31.03.2026 (copy enclosed).

3. As per the aforesaid instructions, Ministries/Departments have been advised to ensure continuity of schemes beyond 31.03.2026, wherever required, up to 30.09.2026 or till the date of approval of the scheme by the competent authority, whichever is earlier. The Expenditure Finance Committee (EFC) meeting was held on 25.03.2026 for continuation of the Revamped RGSA has already approved the proposal for continuation of the scheme for the 16th Finance Commission cycle for the period 2026-27 to 2030-31. However, formal approval of Cabinet is awaited.

4. Pending such approval, all States/UTs are requested to continue implementation of the following activities under RGSA, till further orders or till approval of the scheme by the competent authority, whichever is earlier:

a) Capacity Building and Training activities for elected representatives only;
b) Construction of already approved infrastructure projects, such as Panchayat Bhawans, Panchayat Learning Centres (PLCs) and CSC co-location;
c) Procurement of computers, as per earlier approvals; and
d) Continuation of PMU staff under RGSA at various levels.

However, contractual engagement of BPMU, BPRC and Gram Sabha Mobilisers under the PESA component shall be dealt with separately on a case-to-case basis for which formal proposal has to be submitted to MoPR by each State.

5. Pending approval of continuation of the Scheme by the competent authority, the States/UTs may undertake admissible activities under RGSA up to one-fourth of the physical and financial outlay of the previous year's Annual Action Plan (AAP) approved by the Central Empowered Committee (CEC), on a pro rata basis across eligible components as per the prevailing cost norm subject to the activities mentioned in para 4 above. The activities so undertaken may be reflected in the AAP of the States/UTs for FY 2026–27 and placed before the CEC for consideration, as per extant procedure.

6. This arrangement is intended only to ensure continuity of admissible activities under RGSA till approval of continuation of the Scheme by the competent authority or until 30.09.2026, whichever is earlier.

7. This issues with the approval of the competent authority.

Encl: As above

Yours sincerely,

6/4/26

(Sushil Kumar Lohani)

Copy to:

1. Director General NIRD&PR, Hyderabad
2. All the Divisional Heads of Ministry of Panchayati Raj

} The same principle will be applicable for continuation of activities in the current Financial Year 2026-27 under relevant components of RGSA based on the approval granted in 2025-26.

3. JS & FA: For information please

iv. It may be ensured that the spending limit for the temporarily extended schemes should be within the approved allocation of QEP-I and QEP-II of BE 2026-27. Also, the eligible outlay for the new Scheme in the 16th FC period shall be reduced proportionately.

v. Further, with reference to the D.O letter No.01(01)/PFC-II/2025 dated 2nd January, 2026 from Secretary (Expenditure) addressed to all Secretaries, this is to reiterate that all Ministries/Departments should undertake a comprehensive exercise for rationalization of schemes through merger/consolidation/restructuring etc. in order to reduce the number of Schemes.

This issues with the approval of Secretary (Expenditure).

(Ajith Kumar N.)
Dy. Director General (PFC-I)

To,

i. All Secretaries to the Government of India
ii. All Financial Advisers to the Ministries/Departments,

Copy to:

i. Prime Minister's Office
ii. Cabinet Secretariat
iii. NITI Aayog
iv. Railway Board
v. Internal Circulation

No. CW-II/3/2025-CW-II (e-120426)
Government of India
Ministry of Women and Child Development
(Child Welfare-II Section)

For Official Use/IMMEDIATE

No. 42(02/PF-II/2014
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Public Finance (Central-I) Division

Kartavya Bhawan-01, New Delhi
Dated: 23rd March, 2026

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Appraisal and Approval of Schemes ending on 31st March, 2026 and proposed to be continued in the 16th FC Cycle - Extension of tenure pending completion of Appraisal and Approval - reg

Reference is invited to this Department's OM No. 01(01)/PFC-II/2025 dated 6th June, 2025 whereby Guidelines for Appraisal and Approval of Schemes ending on 31st March 2026 and to be continued in the 16th FC Cycle were issued. In the said OM, this Department had, inter alia, requested all Ministries/Departments to send the Appraisal Memos along with the Third Party Evaluation Reports by 31st October, 2025 so that approval of the Schemes can be obtained from the competent authority well before 31st March 2026.

However, it is seen that so far only a few Ministries/Departments have submitted the Appraisal Notes and got the Schemes appraised by the appropriate forum. Since some of the Ministries/Departments are in the process of revamping and rationalising the Schemes based on Third Party Evaluation, there seems to be a delay in submission of the Appraisal Notes.

Therefore, in the interest of uninterrupted implementation of the on-going Schemes which are ending on 31st March 2026, the following instructions are issued:

i. **Wherever the Ministry /Departments are of the view that submission of Appraisal Notes for continuation of an ongoing Scheme in the 16th FC is likely to get delayed, and that the ongoing scheme should be extended temporarily, they may identify such Schemes requiring temporary extension of tenure, in consultation with their Financial Advisors, and submit the list to this Department by 31st March 2026, along with the reasons/justification for continuation.**

ii. All such Schemes will be extended up to 30th September 2026 or Date of approval of the scheme for the 16th FC cycle by the competent authority, whichever is earlier.

iii. Such temporary extension of the existing scheme shall have the same scope, structure, nature, coverage, cost norms, and other terms & conditions as was applicable for the 15th FC period.